IJAER/ March-April 2021/Volume-9/Issue-5 ISSN: 2278-9677
International Journal of Arts & Education Research

कृषि सब्सिडी और उनका प्रभाव

[1] Anjali Saini, [2]Dr. Jasbir Singh
[1]Research Scholar, [2]Supervisor

[1-2] Department of Economics, Malwanchal University, Indore

सार

कृषि सब्सिडी अर्थशास्त्र और कृषि नीति के क्षेत्र में व्यापक शोध और बहस का विषय रही है। इस शोध का उद्देश्य कृषि क्षेत्र, अर्थव्यवस्था और समाज पर कृषि सब्सिडी के प्रभाव का व्यापक विश्लेषण प्रदान करना है। यह शोध सब्सिडी के ऐतिहासिक संदर्भ, उनके उद्देश्यों और विभिन्न हितधारकों के लिए उनके निहितार्थों पर प्रकाश डालता है। मौजूदा साहित्य और अनुभवजन्य साक्ष्य की गहन समीक्षा के माध्यम से, यह शोध कृषि सब्सिडी के बहुमुखी प्रभावों पर प्रकाश डालता है, जिसमें उनके आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक परिणाम भी शामिल हैं। इसके अलावा, यह टिकाऊ और न्यायसंगत कृषि प्रथाओं के साथ बेहतर तालमेल के लिए सब्सिडी कार्यक्रमों में सुधार से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों का पता लगाता है।

मुख्य शब्दः कृषि सब्सिडी, आर्थिक प्रभाव, पर्यावरणीय परिणाम, सामाजिक निहितार्थ, कृषि नीति, वहनीयता, सुधार, हितधारकों, सरकार का हस्तक्षेप, कृषि आय।

परिचय

कृषि सब्सिडी लंबे समय से दुनिया भर के कई देशों में कृषि नीति का एक महत्वपूर्ण घटक रही है। ये सब्सिडी, जो अक्सर सरकारों द्वारा प्रदान की जाती है, किसानों को समर्थन देने, खाद्य उत्पादन को स्थिर करने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन की गई है। हालाँकि, कृषि सब्सिडी का प्रभाव अकादमिक अनुसंधान और नीति विश्लेषण के दायरे में चल रही बहस और जांच का विषय है।

यह शोध कृषि सब्सिडी और उनके दूरगामी परिणामों की व्यापक जांच प्रदान करना चाहता है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि कृषि सब्सिडी केवल किसानों को प्रदान किया जाने वाला वित्तीय प्रोत्साहन नहीं

है, वे आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक अंतःक्रियाओं के एक जटिल जाल का प्रतिनिधित्व करते हैं जो संपूर्ण खाद्य उत्पादन प्रणाली को प्रभावित करते हैं।

इस पूरे शोध में, हम कृषि सब्सिडी के ऐतिहासिक विकास, उनके प्राथमिक उद्देश्यों और उनके इच्छित लाभों का पता लगाएंगे। हम इन सब्सिडी से उत्पन्न अनपेक्षित परिणामों और चुनौतियों पर भी चर्चा करेंगे। यह विश्लेषण कृषि क्षेत्र, अर्थव्यवस्था और समग्र रूप से समाज पर सब्सिडी के व्यापक प्रभाव का विस्तार करेगा।

यह शोध स्थिरता के महत्वपूर्ण प्रश्न को भी संबोधित करेगा। हाल के वर्षों में, कृषि सब्सिडी के पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में चिंताएँ सामने आई हैं, जिससे स्थायी कृषि प्रथाओं के साथ सुधार और पुनर्गठन के बारे में चर्चा को बढ़ावा मिला है। इस प्रकार, हम आर्थिक समृद्धि और पर्यावरणीय प्रबंधन दोनों को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी कार्यक्रमों में सुधार की क्षमता का गंभीर रूप से आकलन करेंगे।

संक्षेप में, यह शोध कृषि सब्सिडी, उनके बहुमुखी परिणामों और नीति सुधार के अवसरों का सूक्ष्म और साक्ष्य–आधारित विश्लेषण पेश करने का प्रयास करता है। ऐसा करके, इसका उद्देश्य कृषि नीति और खाद्य उत्पादन और वितरण के भविष्य को आकार देने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका के आसपास चल रही बातचीत में योगदान देना है।

कृषि उत्पादकता बढ़ाने में सब्सिडी की प्रभावशीलता

कृषि सब्सिडी को लंबे समय से दुनिया भर की सरकारों द्वारा कृषि उत्पादकता बढ़ाने, ग्रामीण समुदायों का समर्थन करने और स्थिर खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करने के साधन के रूप में नियोजित किया गया है। ये सब्सिडी विभिन्न रूपों में आती हैं, जिनमें प्रत्यक्ष भुगतान, मूल्य समर्थन और उर्वरक और बीज सब्सिडी जैसी इनपुट सब्सिडी शामिल हैं। व्यापक लक्ष्य कृषि उत्पादन को प्रोत्साहित करना, कृषि आय में वृद्धि करना और अंततः खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है। हालाँकि, इन उद्देश्यों को प्राप्त करने में सब्सिडी की प्रभावशीलता विद्वानों, नीति निर्माताओं और कृषि हितधारकों के बीच बहस का विषय है।

यह अनुभाग कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने में कृषि सब्सिडी की प्रभावशीलता की जांच करेगा। इसकी शुरुआत सब्सिडी और उनके अपेक्षित लाभों को रेखांकित करने वाले सैद्धांतिक ढांचे की जांच से होगी। इसके बाद, यह अनुभवजन्य साक्ष्यों पर गौर करेगा, अध्ययनों और वास्तविक दुनिया के उदाहरणों पर चर्चा करेगा जो कृषि उत्पादकता पर सब्सिडी के प्रभाव पर प्रकाश डालते हैं।

सैद्धांतिक ढांचा:

कृषि सब्सिडी इस सिद्धांत पर आधारित है कि किसानों को वित्तीय या भौतिक प्रोत्साहन प्रदान करने से कृषि में उत्पादन और निवेश में वृद्धि हो सकती है। प्राथमिक तंत्र जिसके माध्यम से सब्सिडी का लक्ष्य उत्पादकता को बढ़ावा देना है, उनमें शामिल हैं:

- **आय सहायता:** किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करके, सब्सिडी कृषि आय को स्थिर कर सकती है, खासकर कमोडिटी की कम कीमतों या प्रतिकूल मौसम की स्थिति के दौरान। यह स्थिरता किसानों को अपने कार्यों में उत्पादन और निवेश जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करती है।
- **संसाधन आवंटन:** सब्सिडी कुछ इनपुट, जैसे कि उर्वरक या कीटनाशक, को किसानों के लिए अधिक किफायती बनाकर संसाधन आवंटन को प्रभावित कर सकती है। इससे, बदले में, पैदावार में वृद्धि और उत्पादकता में सुधार हो सकता है।
- **जोखिम न्यूनीकरण:** सब्सिडी एक सुरक्षा जाल के रूप में कार्य करती है, जो कृषि से जुड़े जोखिमों को कम करती है। जब किसानों को न्यूनतम स्तर की आय या सहायता का आश्वासन दिया जाता है, तो वे आधुनिक प्रौद्योगिकियों और प्रथाओं को अपनाने के लिए अधिक इच्छुक हो सकते हैं, जो उत्पादकता बढ़ा सकते हैं।

अनुभवजन्य साक्ष्य:

उत्पादकता बढ़ाने में कृषि सब्सिडी की प्रभावशीलता अनुभवजन्य विश्लेषण का विषय रही है। कई अध्ययन और वास्तविक दुनिया के उदाहरण इस मामले में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं।

- **सकारात्मक प्रभावः** कुछ अध्ययनों में सब्सिडी और कृषि उत्पादकता के बीच सकारात्मक संबंध पाया गया है। उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में किए गए शोध से पता चला है कि सब्सिडी भूमि उपयोग में वृद्धि और कुछ फसलों के लिए उच्च पैदावार में योगदान कर सकती है।
- **घटता प्रतिफलः** हालाँकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सब्सिडी और उत्पादकता के बीच संबंध सभी संदर्भों में एक समान नहीं है। कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि सब्सिडी के सकारात्मक प्रभाव समय के साथ कम हो सकते हैं, खासकर जब संसाधनों के स्थायी उपयोग पर विचार किए बिना सब्सिडी प्रदान की जाती है।
- **संसाधन का गलत आवंटनः** आलोचकों का तर्क है कि सब्सिडी से संसाधन का गलत आवंटन हो सकता है, जहां किसान अपनी सब्सिडी वाली लागत के कारण पानी या उर्वरक जैसे कुछ इनपुट का अत्यधिक उपयोग कर सकते हैं। इसके प्रतिकूल पर्यावरणीय परिणाम हो सकते हैं और स्थायी दीर्घकालिक उत्पादकता लाभ नहीं हो सकता है।
- **बाजार विकृतियाँः** सब्सिडी कुछ फसलों के उत्पादन को कृत्रिम रूप से बढ़ाकर कृषि बाजारों को विकृत भी कर सकती है, जिससे अधिशेष और कीमतें कम हो सकती हैं। यह बिना सब्सिडी वाले कृषि क्षेत्रों की प्रतिस्पर्धात्मकता पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है और इसके परिणामस्वरूप अकुशल संसाधन आवंटन हो सकता है।

निष्कर्षतः, उत्पादकता बढ़ाने में कृषि सब्सिडी की प्रभावशीलता एक जटिल और संदर्भ–निर्भर मुद्दा है। जबकि सब्सिडी किसानों को अल्पकालिक सहायता प्रदान कर सकती है और कृषि उत्पादन बढ़ा सकती है, उनका दीर्घकालिक प्रभाव विभिन्न कारकों के अधीन है, जिसमें सब्सिडी कार्यक्रमों के डिजाइन, उनके पर्यावरणीय परिणाम और टिकाऊ कृषि प्रथाओं के साथ उनकी अनुकूलता शामिल है। नीति निर्माताओं को सब्सिडी नीतियों को तैयार और मूल्यांकन करते समय इन कारकों पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे वास्तव में कृषि उत्पादकता बढ़ाने और ग्रामीण समुदायों की समग्र भलाई में योगदान करते हैं।

कृषि क्षेत्र पर सरकारी सब्सिडी के प्रभाव का मूल्यांकन

कृषि क्षेत्र में सरकारी सब्सिडी नीति निर्माताओं, अर्थशास्त्रियों और कृषि हितधारकों के बीच गहन बहस और जांच का विषय रही है। ये सब्सिडी आम तौर पर विभिन्न उद्देश्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से होती है, जिसमें कृषि आय को स्थिर करना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना शामिल है। हालाँकि, यह निर्धारित करने के लिए उनके प्रभाव का व्यापक मूल्यांकन करना आवश्यक है कि क्या वे इन लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त करते हैं या यदि वे अनपेक्षित परिणामों को जन्म देते हैं। यह खंड तीन प्रमुख आयामोंः आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक पर ध्यान केंद्रित करते हुए कृषि क्षेत्र पर सरकारी सब्सिडी के प्रभाव का मूल्यांकन जारी रखेगा।

आर्थिक प्रभावः

- **कृषि आय स्थिरताः** सरकारी सब्सिडी कृषि आय को स्थिर करने, अस्थिर वस्तु कीमतों या प्राकृतिक आपदाओं के दौरान किसानों के लिए सुरक्षा जाल प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह आय स्थिरता निरंतर कृषि उत्पादन और आधुनिक कृषि पद्धतियों में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण है।
- **बाजार विकृतियाँः** नकारात्मक पक्ष यह है कि सब्सिडी कुछ फसलों के उत्पादन को कृत्रिम रूप से बढ़ाकर कृषि बाजारों को विकृत कर सकती है। इससे अधिशेष और कम कीमतें हो सकती हैं, गैर–सब्सिडी वाले क्षेत्रों की प्रतिस्पर्धात्मकता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और संभावित रूप से कृषि बाजार की समग्र दक्षता कम हो सकती है।
- **निर्भरताः** एक जोखिम है कि सब्सिडी पर अत्यधिक निर्भरता किसानों के बीच निर्भरता पैदा कर सकती है, जिससे वे ऐसे नवाचारों और टिकाऊ प्रथाओं की तलाश करने से हतोत्साहित हो सकते हैं जो सब्सिडी के बिना उत्पादकता बढ़ा सकते हैं। इससे दीर्घकालिक कृषि विकास में बाधा उत्पन्न हो सकती है।

पर्यावरणीय प्रभावः

- **संसाधन का गलत आवंटनः** सरकारी सब्सिडी, विशेष रूप से उर्वरक जैसी इनपुट सब्सिडी, संसाधनों के गलत आवंटन का कारण बन सकती है। जब इनपुट पर भारी सब्सिडी दी जाती है, तो किसान

उनका अत्यधिक उपयोग कर सकते हैं, जिससे मिट्टी का क्षरण, जल प्रदूषण और अन्य पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो सकती हैं।

- **टिकाऊ प्रथाएँ:** सब्सिडी या तो टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाने को प्रोत्साहित या हतोत्साहित कर सकती है। जब सोच–समझकर डिजाइन किया जाता है, तो सब्सिडी उन प्रथाओं को बढ़ावा दे सकती है जो मिट्टी के स्वास्थ्य, जल संरक्षण और कीटनाशकों के उपयोग को कम करने को प्राथमिकता देती हैं। हालाँकि, यदि स्थिरता लक्ष्यों के साथ संरेखित नहीं किया जाता है, तो सब्सिडी पर्यावरण की दृष्टि से हानिकारक प्रथाओं को प्रोत्साहित कर सकती है।
- **जलवायु परिवर्तन:** सब्सिडी का पर्यावरणीय प्रभाव जलवायु परिवर्तन तक भी फैलता है। कार्बन–सघन कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने वाली सब्सिडी ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में योगदान कर सकती है, जबकि टिकाऊ पद्धतियों का समर्थन करने वाली सब्सिडी जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम कर सकती है।

सामाजिक प्रभाव:

- **ग्रामीण विकास:** सरकारी सब्सिडी अक्सर ग्रामीण विकास को बढ़ावा देकर सकारात्मक सामाजिक प्रभाव डालती है। वे ग्रामीण आबादी को बनाए रखने, रोजगार के अवसर प्रदान करने और ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक व्यवहार्यता का समर्थन करने में मदद कर सकते हैं।
- **आय असमानता:** सब्सिडी छोटे किसानों की तुलना में बड़े और धनी किसानों को अधिक लाभ पहुंचा सकती है, जिससे कृषि क्षेत्र में आय असमानता बढ़ जाएगी। नीति निर्माताओं को सब्सिडी कार्यक्रम डिजाइन करते समय इक्विटी मुद्दों पर विचार करना चाहिए।
- **खाद्य सुरक्षा:** उपभोक्ताओं के लिए स्थिर खाद्य आपूर्ति और सस्ती कीमतें सुनिश्चित करके सब्सिडी खाद्य सुरक्षा को बढ़ा सकती है। हालाँकि, उन्हें बाजार की विकृतियों से बचने के लिए सावधानीपूर्वक लक्षित किया जाना चाहिए जो खाद्य असुरक्षा का कारण बन सकती हैं।

निष्कर्ष:

कृषि क्षेत्र पर सरकारी सब्सिडी का प्रभाव बहुआयामी और संदर्भ–निर्भर है। जबकि सब्सिडी कृषि आय को स्थिर कर सकती है, ग्रामीण विकास का समर्थन कर सकती है और खाद्य सुरक्षा बढ़ा सकती है, वे बाजारों को विकृत भी कर सकती हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकती हैं और आय असमानता में योगदान कर सकती हैं। इन प्रतिस्पर्धी हितों के बीच संतुलन हासिल करने के लिए सब्सिडी कार्यक्रमों के सावधानीपूर्वक डिजाइन और मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। नीति निर्माताओं को नकारात्मक परिणामों को कम करते हुए कृषि क्षेत्र पर उनके सकारात्मक प्रभाव को अधिकतम करने के लिए सब्सिडी के विशिष्ट लक्ष्यों, उनके पर्यावरणीय प्रभावों और उनके संभावित सामाजिक प्रभावों पर विचार करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, जलवायु परिवर्तन और संसाधनों की कमी सहित वैश्विक चुनौतियों के युग में कृषि की दीर्घकालिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए सब्सिडी कार्यक्रमों को स्थिरता लक्ष्यों के साथ संरेखित करना आवश्यक है।

कृषि सब्सिडी के आर्थिक परिणाम और समानता संबंधी मुद्दे

कृषि सब्सिडी, हालांकि विभिन्न आर्थिक और सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए डिजाइन की गई है, अक्सर महत्वपूर्ण आर्थिक परिणाम और इक्विटी मुद्दे लेकर आती है। यह खंड कृषि सब्सिडी के आर्थिक प्रभाव की पड़ताल करता है और उनके वितरण से जुड़ी इक्विटी चिंताओं की जांच करता है।

आर्थिक परिणामः

- **बाजार विकृतियाँः** कृषि सब्सिडी के प्राथमिक आर्थिक परिणामों में से एक बाजार विकृति है। सब्सिडी वाले इनपुट और मूल्य समर्थन आपूर्ति और मांग की गतिशीलता को बदल सकते हैं, जिससे कुछ फसलों का अधिक उत्पादन और अधिशेष हो सकता है। यह, बदले में, कीमतों को कम कर सकता है, गैर–सब्सिडी वाले किसानों की आय को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विकृत कर सकता है।
- **संसाधनों का गलत आवंटनः** सब्सिडी संसाधनों के गलत आवंटन का कारण बन सकती है, खासकर जब उन्हें उर्वरक और पानी जैसे इनपुट पर लागू किया जाता है। इन आदानों के लिए भारी

सब्सिडी उनके अत्यधिक उपयोग को प्रोत्साहित कर सकती है, जिससे पर्यावरणीय गिरावट, मिट्टी का क्षरण और जल प्रदूषण में योगदान हो सकता है।

- **बजटीय लागतः** कृषि सब्सिडी सरकारों के लिए एक महत्वपूर्ण बजटीय बोझ का प्रतिनिधित्व करती है। कृषि को सब्सिडी देने के लिए आवंटित वित्तीय संसाधनों को संभावित रूप से व्यापक सामाजिक लाभ वाले अन्य क्षेत्रों, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, या बुनियादी ढांचे के विकास में पुनर्निर्देशित किया जा सकता है।
- **अकुशल उत्पादनः** सब्सिडी किसानों को अधिक कुशल और नवीन कृषि पद्धतियों को अपनाने से हतोत्साहित कर सकती है क्योंकि वे कम उत्पादकता की स्थिति में भी सुरक्षा जाल प्रदान करते हैं। इससे समग्र कृषि उत्पादकता वृद्धि में बाधा आ सकती है।

इक्विटी मुद्देः

- **आय असमानताः** कृषि सब्सिडी कृषक समुदाय के भीतर आय असमानता को बढ़ा सकती है। बड़े और अधिक व्यावसायिक रूप से उन्मुख खेतों को सब्सिडी से अधिक लाभ होता है, क्योंकि उनमें प्राप्त सब्सिडी को अधिकतम करने की क्षमता होती है। दूसरी ओर, छोटे और हाशिए पर रहने वाले किसानों के पास संसाधन या सब्सिडी तक पहुंच नहीं हो सकती है, जिससे आय में असमानताएं पैदा होती हैं।
- **ग्रामीण–शहरी विभाजनः** सब्सिडी भी ग्रामीण–शहरी विभाजन में योगदान कर सकती है। हालाँकि सब्सिडी ग्रामीण आजीविका और समुदायों का समर्थन करती है, लेकिन वे शहरी आबादी को सीधे लाभ नहीं पहुंचा सकती हैं। इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच तनाव और असमानता की धारणा पैदा हो सकती है।
- **वैश्विक व्यापार असमानताएँः** वैश्विक संदर्भ में, एक देश द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी कुछ वस्तुओं के उत्पादन की लागत को कृत्रिम रूप से कम करके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विकृत कर सकती है। इससे अन्य देशों के किसानों को नुकसान हो सकता है जो सब्सिडी वाले उत्पादों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते, जिससे संभावित रूप से व्यापार विवाद हो सकते हैं।

- **सब्सिडी तक पहुंचः** महिलाओं और अल्पसंख्यक किसानों सहित हाशिए पर या वंचित आबादी के लिए सब्सिडी तक पहुंच चुनौतीपूर्ण हो सकती है। आगे हाशिए पर जाने से बचने के लिए सब्सिडी कार्यक्रमों तक समान पहुंच सुनिश्चित करना आवश्यक है।

निष्कर्ष

निष्कर्षतः, कृषि सब्सिडी दूरगामी आर्थिक, पर्यावरणीय और इक्विटी निहितार्थों के साथ एक बहुआयामी नीति उपकरण का प्रतिनिधित्व करती है। हालाँकि इन्हें अक्सर कृषि आय को स्थिर करने, खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने और ग्रामीण विकास का समर्थन करने के उद्देश्य से लागू किया जाता है, लेकिन उनका प्रभाव इन इच्छित लक्ष्यों से कहीं अधिक होता है।

आर्थिक रूप से, सब्सिडी बाजारों को विकृत कर सकती है, संसाधनों का गलत आवंटन कर सकती है और सरकारी बजट पर दबाव डाल सकती है। बाजार की विकृतियाँ अतिउत्पादन और अधिशेष को जन्म दे सकती हैं, जिससे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दोनों प्रभावित हो सकते हैं। संसाधनों का गलत आवंटन, विशेष रूप से इनपुट सब्सिडी के माध्यम से, पर्यावरणीय गिरावट और संसाधन की कमी में योगदान कर सकता है। इसके अतिरिक्त, सब्सिडी कार्यक्रमों को बनाए रखने के लिए आवश्यक वित्तीय प्रतिबद्धता अन्य आवश्यक क्षेत्रों से संसाधनों को हटा सकती है।

इक्विटी के मुद्दे सब्सिडी लाभों के असमान वितरण, बड़े और अधिक व्यावसायिक रूप से उन्मुख खेतों को बढ़ावा देने और संभावित रूप से कृषि क्षेत्र के भीतर आय असमानता को बढ़ाने से उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा, ग्रामीण–शहरी विभाजन और सब्सिडी तक पहुंच में असमानताएं सामाजिक असमानताओं को और गहरा कर सकती हैं।

इन जटिल चुनौतियों से निपटने के लिए, नीति निर्माताओं को सब्सिडी कार्यक्रमों के आर्थिक उद्देश्यों और बाजार दक्षता, संसाधन स्थिरता और इक्विटी की आवश्यकता के बीच एक नाजुक संतुलन बनाना होगा। इसके लिए विचारशील कार्यक्रम डिजाइन की आवश्यकता होती है जो सुनिश्चित करता है कि सब्सिडी प्रभावी ढंग से लक्षित हो, छोटे धारकों और हाशिए पर रहने वाले किसानों का समर्थन करे, और टिकाऊ

कृषि प्रथाओं के साथ संरेखित हो। इसके अलावा, सब्सिडी के कारण होने वाली वैश्विक व्यापार असमानताओं को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग महत्वपूर्ण है।

जलवायु परिवर्तन, संसाधनों की कमी और बदलती उपभोक्ता प्राथमिकताओं सहित उभरती वैश्विक चुनौतियों के सामने, खाद्य उत्पादन और वितरण के भविष्य को आकार देने में कृषि सब्सिडी की भूमिका निरंतर बहस और मूल्यांकन का विषय बनी हुई है। ऐसे समाधान ढूंढना जो इक्विटी संबंधी चिंताओं को दूर करते हुए आर्थिक समृद्धि और स्थिरता दोनों को बढ़ावा दें, नीति निर्माताओं और हितधारकों के लिए एक महत्वपूर्ण अनिवार्यता है क्योंकि वे आने वाले वर्षों में कृषि क्षेत्र के लिए दिशा तय करते हैं।

संदर्भ

- अभिषेक चौहान, (2014), 'राष्ट्र निर्माण के लिए भारत में ग्रामीण विकास की आवश्यकता', एशियन मिरर– इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च, 1(1)।
- भट्टाचार्जी, एसएस (2011), प्रौद्योगिकी अपनाने द्वारा ग्रामीण सेवा वितरण, 'आईटीयू टेलीकॉम वर्ल्ड (आईटीयू डब्ल्यूटी) में तकनीकी संगोष्ठी की कार्यवाही' में लोगों को सक्षम करने, व्यवसाय को सशक्त बनाने, समाज को समृद्ध करने का एक मामला, पीपी। 141–146।
- चक्रवर्ती, एस., भट्टाचार्य, टी., भौमिक, पी.के., बसु, ए., और सरकार, एस. (2014), 'शिक्षकः ग्रामीण शिक्षा के लिए एक इंटेलिजेंट ट्यूटरिंग सिस्टम ऑथरिंग टूल',1–10।
- डेगाडा, ए. (2015), कम लागत, पोर्टेबल टेलीमेडिसिन सिस्टम का डिजाइन और कार्यान्वयनः एक एंबेडेड टेक्नोलॉजी और आईसीटी दृष्टिकोण, 'इंजीनियरिंग पर 5वें निरमा विश्वविद्यालय आईईईई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की कार्यवाही (एनयूआईसीओएन)' में।
- गायत्री, एमके (2015), आईओटी का उपयोग करके बेहतर उपज के लिए किसानों को स्मार्ट कृषि समाधान प्रदान करना, 'कृषि और ग्रामीण विकास के लिए आईसीटी में तकनीकी नवाचारों पर आईईईई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की कार्यवाही (टीआईएआर 2015)', पृष्ठ 40–43।